अध्यक्ष महोदय

20 MAR 2002 असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बि० स० मु० (एल० ए०) 115—मोनो—500—10-3-2000—

अल्प सूचित प्रश्न संख्या -11 पूरक क्रमश:

क्रमश:

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा (मंत्री) : प्रारम्भ करते हैं और दूसरे माह व्यवसायिक मार्गदर्शन के लिए पटना स्थित नियोजनालय में एक पुस्तकालय की स्थापना की गयी है । तीसरा, टेलीफोन द्वारा कोई भी व्यक्ति रोजगार के संबंध में -हेल्पलाईन आरम्भ किए हैं, यह तीन चीज हम मार्गदर्शन के लिए, व्यवसायिक मार्गदर्शन के लिए प्रारम्भ किए हैं -जो विभाग ने काम किया है, हम पद सृजित नहीं करते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, हम रास्ता बताते हैं ।

श्री चन्द्र मोहन राय : रास्ता बताने के बाद भी उसका फल क्या सामने आया है -सरकार के सामने कोई योजना है, आपका जो रेशियो है 20 लाख के अगेंस्ट में मात्र 451 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सका है, उस अनुपात में सुधार हो और बिहार के नौजवानों को रोजगार मुहैय्या कराने के लिए आपकी क्या येजना है ?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा (मंत्री) : आपके सुझावों पर विचार करेंगे ।

अल्प सूचित प्रश्न संख्या -12

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा (मंत्री) : (1)--स्वीकारात्मक है । वर्ष 2000-2001 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्वीकृत पथों के कार्यान्वयन हेतु निविदाएं आमंत्रित कर निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है । अबतक 50 पैकेजों के लिए कार्य आवंटित करने का आदेश निर्गत किया जा चुका है । प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के वर्ष 2001-2002 की योजना भारत सरकार को भेजी गई । भारत सरकार के परामर्श पर 34 जिलों के लिए पुनरीक्षित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है शेष 4 जिलों के लिए योजना स्वीकृत है ।

(2) दूसरे राज्यों को इस योजना के कार्यान्वयन के विषय में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(3) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्यान्वयन किया जारहा है ।

अध्यक्ष : इस संबंध में माननीय सदस्य स्वयं उपस्थित होकर देखे ही हैं और इसपर

टर्न-26/ज्योति/20-3-2002

कार्रवाई हुई ही है । 18 तारीख को जो हमलोग 5 बजे शाम में बैठे थे इस दिशा में विस्तृत रूप से समीक्षा की जा चुकी है ।

श्री भोला प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मैंने पूछा है वह सदन की संपत्ति है और मैं चाहता हूँ कि सरकार के स्तर पर और आपके तत्वाधान में जो भी निर्णय हुए हैं वह सदन की सम्पत्ति बन जाय ।

अध्यक्ष : बन जायेगी ।

श्री भोला प्रसाद सिंह: इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि दो वर्षों में एक योजना भी एक वित्तीय वर्ष की लागू नहीं हुई और सरकार इस कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए क्या कोई विशेष प्रयास करना चाहती है ताकि तत्परतापूर्वक हम दोनों वर्ष की योजना को समय रहते कार्यान्वित कर सके ?

अध्यक्ष: 18 तारीख को हुई बैठक की कार्रवाही की जानकारी सभी माननीय सदस्यों को दे दी जायेगी । इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी को कुछ निदान हो तो बतला दीजिये ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा(मंत्री): मेरा कहना है कि सेन्ट्रलाईज्ड टेण्डर एक डेट पर होना था और मार्च में हमको पैसा मिला है वह भी अंत में मिला है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, दलीय नेताओं के समक्ष, माननीय मंत्री की उपस्थिति में जिसमें विपक्ष के सम्मानीय विपक्ष के नेता थे, दलीय नेतागण थे उसमें विस्तृत रूप से सरकार के पदाधिकारियों के साथ बातें हो चुकी है ।

श्री उमाशंकर सिंह : क्यों नहीं इस प्रश्न को स्थगित कर दिया गया ?

अध्यक्ष: हम चाहते थे कि इन बातों की जानकारी सबको दे दें ।

श्री०क्रमशः

श्री भोला प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि विभाग में अभियंता प्रमुख, अधीक्षण अभियंता के नहीं रहने के कारण यह योजना जिसको समय पर कार्यान्वित होना चाहिए था नहीं हुआ तो क्या सरकार दूसरे राज्यों से इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जैसे मध्य प्रदेश में डिवीजनल कमीश्नर को अधिकार दिया है क्या सरकार उसको ध्यान में रखते हुए इस परिस्थिति में डिवीजनल कमीश्नर को यह अधिकार देकर इस योजना को कार्यान्वित कराना चाहती है ?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा (मंत्री): विचार विमर्श हुआ, इस पर सरकार कार्रवाई कर रही है ।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार में जिन अधिकारियों के गड़बड़ी के चलते प्रधानमंत्री सड़क योजना का प्रस्ताव भारत सरकार से दो बार तीन तीन बार लौटाया गया है क्या उन अधिकारियों को दंडित करने के लिए सरकार उन अधिकारियों को चिन्हित करना चाहती है ?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा (मंत्री): किसी पदाधिकारी की गड़बड़ी का कोई सवाल नहीं है ।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेο विοदलο): महोदय, इतने महत्व का सवाल है । सर्वदलीय बैठक जो हुई थी उस बैठक की पूरी कार्यवाही सदन के सामने आनी चाहिए ताकि प्रेस को और बिहार की जनता को मालूम हो सके ।

अध्यक्ष: वह दे देंगे ।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेο विοदलο): अध्यक्ष महोदय, सबसे गंभीर बात यह आयी उस बैठक में कि जो 31 मार्च को 150 करोड़ मिला वह साल का अंत हो गया । इसलिए राशि खर्च नहीं हो पायी चूंकि इंजीनियर इन चीफ नहीं थे, तीन महीना पद खाली रहा इसके बाद जिनको बनाया गया वे भी रिटायर कर गए इसके बाद जिनको बनाया गया वे डबल चार्ज में हैं । दो तिहाई मुख्य अभियंता नहीं हैं । अधीक्षण अभियंता के पद आधे से ज्यादा खाली पड़े हुए हैं । चीफ सेक्रेटरी भी बैठक में मौजूद थे । वहीं निष्कर्ष निकला कि योजना में इसलिए विलंब हुआ कि सैंक्शनिंग अथोरिटी नहीं था । इससे शर्म की बात इस सरकार के लिए क्या हो सकती है । 150 करोड़ रुο पड़ा रह गया और [illegible] सैंक्शनिंग अथोरिटी नहीं था महोदय, मैं चाहूंगा कि सारी बातें सदन के सामने आनी चाहिए ।

27
टर्न-27/ 20.3.02
विजय।

150 करोड़ पिछले साल का और इस साल का 150 करोड़ रू0 खर्च नहीं हुआ।

अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को 18.3.02 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत करा दूंगा। सरकार सचेष्ट है, चिंतित है।

(व्यवधान)